महत्वाकांक्षाओं के आइने में शिक्षा

फरवरी* माह में केन्द्रीय बजट आ गया है। यह इस सरकार का अंतिम बजट है। पिछले पांच सालों में कई क्षेत्रों में तेजी से बदलाव हुए हैं या बदलाव के वादे किए गए हैं इनमें से स्कूली शिक्षा भी एक है। शिक्षा प्रणाली में कई संरचनात्मक बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव, उच्च शिक्षा स्तर पर उच्च जाति के गरीब छात्रों के लिए 10 प्रतिशत कोटे का प्रावधान, समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत, फेल न करने की नीति की समाप्ति से लेकर जिला स्तरीय राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षणों तक यह बदलाव व्यापक स्तर पर किए गए हैं या किए जाने की इच्छा सरकार की रही है। इनमें से कुछ पार चढ़ पाए हैं और कुछ का भविष्य क्या होगा कहा नहीं जा सकता। माध्यमिक शिक्षा मिशन व सर्वशिक्षा अभियान को मिला कर समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिला स्तरीय राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के एक दौर के परिणाम पिछली साल आ चुके हैं। परीक्षा लेने व फेल करने की नीति लागू हो चुकी है मगर बहुप्रचारित नई शिक्षा नीति सिर्फ प्रस्ताव तक सिमट कर रह गई और इस सरकार के लिए अब एक स्वप्न में तब्दील हो गई।

इस सरकार ने खास कर हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात जो बहुत दोहराई थी वह थी विश्व में सबसे युवा आबादी वाला देश होने की। मगर आंकड़े बताते हैं कि हम इस 'जनसांख्यकीय लाभांश' (डेमाग्राफिक डिविडेंड) का सदोपयोग करने में विफलता की ओर बढ़ रहे हैं।

लोकतांत्रिक समाज में नागरिक के निर्माण की जिम्मेदारी शिक्षा के कंधों पर आती है मगर शिक्षा पर खर्च लगातार कम होता गया है। नीचे दिया गया चित्र बताता है कि पिछले पांच सालों में यह कुल केन्द्रीय बजट के 4.6 प्रतिशत से घट कर 3.5 प्रतिशत पर पहुंच गया है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 0.64 प्रतिशत से घट कर 0.45 प्रतिशत रह गया है।

चित्र : केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा पर किया जाने वाला बजटीय व्यय (प्रतिशत में)

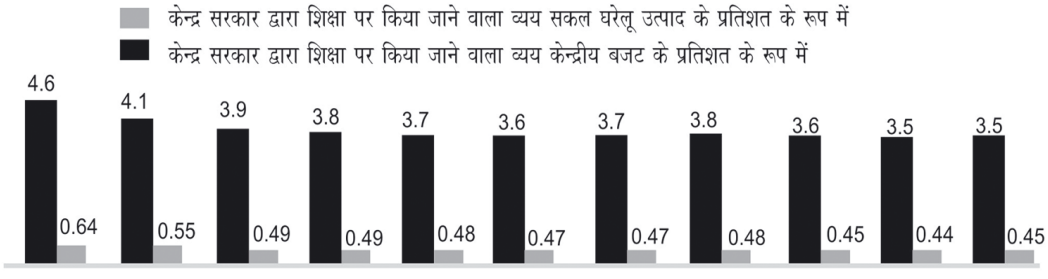

स्रोत : विभिन्न वर्षों के बजट दस्तावेजों का सीबीजीए द्वारा समेकन

वा. = वास्तविक बजट; **ब.अ.** = बजट अनुमान; **स.अ.** = संशोधित अनुमान

* फरवरी, 2019

सारणी : स्कूली शिक्षा की कुछ विशेष योजनाओं को बजट आवंटन (करोड़ रुपयों में)

योजनाएं	2014–15 वास्तविक	2015–16 वास्तविक	2016–17 वास्तविक	2017–18 वास्तविक	2018–19 संशोधित अनुमान	2019–20 बजट अनुमान
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	29070	27066	27616	28209	30834	36472
सर्वशिक्षा अभियान	24097	21661	21685	23484	26129	––
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	3398	3563	3698	4033	4164	––
समग्र शिक्षा अभियान	––	––	––	––	––	36322
मध्याह्न भोजन	10523	9145	9475	9092	9949	11000
शिक्षक प्रशिक्षण व वयस्क शिक्षा	1158	916	817	691	541	––
शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाना	500	489	495	478	480	––
केन्द्रीय विद्यालय संगठन	3243	3278	3987	4997	5007	4862
नवोदय विद्यालय समिति	2013	2285	2620	3185	3213	3068
राष्ट्रीय बालिका मा. शिक्षा की प्रोत्साहन योजना	––	154	45	292	256	100
अल्प संख्यकों के विकास लिये अम्ब्रेला प्रोग्राम	119	296	109	108	120	120

स्रोत : विभिन्न वर्षों के बजट दस्तावेजों का सीबीजीए द्वारा समेकन

हमारी शिक्षा प्रणाली का जोर इन पिछले सालों में निवेश की बजाए परिणाम पर केन्द्रित हो गया है। इसके परिणामस्वरूप मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून (आरटीई) में गुणावत्ता पूर्ण शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए जो न्यूनतम प्रावधान किए गए हैं उन्हें भी पूरा करना संभव नहीं हो पाया है। शिक्षा केन्द्र व राज्यों की साझी जिम्मेदारी है इसका फायदा उठाते हुए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद से केन्द्र सरकार ने अपनी ज्यादातर जिम्मदारियों को राज्य के पाले में धकेल दिया है। स्कूलों की हालत सीखने के मामले में लगातार गिरती जा रही है। और इसकी ठोस वजहें भी हैं। सरकार ने हाल ही में आरटीई में संशोधन कर शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता हासिल करने की समय सीमा सन् 2015 से बढ़ा कर 2019 कर दी है। मौजूदा 64.41 लाख शिक्षकों में से 11 लाख अभी भी अप्रशिक्षित हैं। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए आवंटित किया जाने वाला बजट 2014-15 से अभी तक कभी भी 500 करोड़ रुपये की सीमा के पार नहीं जा पाया यह इतने बड़ी शिक्षा प्रणाली के सापेक्ष ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है और संरकार की मंशा को सवालों के घेरे में ला खड़ा करता है।

अप्रशिक्षित शिक्षकों की समस्या को सर्वशिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के तहत आयोजित किए जाने वाले सेवाकालीन प्रशिक्षणों के जरिए हल करने की कोशिश होती रही है यह अपने आप में एक विवादित मुद्दा है क्योंकि इसमें यह मान्यता निहित है कि शिक्षक बनने के लिए किसी प्रकार के सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण या अध्यापक शिक्षा की जरूरत नहीं है और कुछ दिनों के सेवा कोलीन प्रशिक्षणों के बल पर योग्य शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। क्या हम कभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे चिकित्सकों की कल्पना कर सकते हैं जिन्हें बिना किसी पूर्व शिक्षण या प्रशिक्षण के ऑपरेशन करने की इजाजत दे दी गई हो और फिर कुछ दिनों के लिए सेवा कालीन प्रशिक्षण आयोजित कर उन्हें योग्य चिकित्सक की मान्यता दे दी गई हो। यह तुलना हालांकि नहीं की जानी चाहिए किन्तु स्थिति की गंभीरता को महसूस करवाने के लिए इसकी जरूरत यहां थी। इन सेवा कालीन प्रशिक्षणों की गुणवत्ता भी संदेह के घेरे में रही है ऐसे में हम कैसे हमारे देश की भावी पीढ़ी की शिक्षा की जिम्मेदारी इन शिक्षकों के कंधों पर छोड़ सकते हैं। दूसरे

का प्रशिक्षणों को बजट बेहद कम होता है। यह सर्वशिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन के प्रशिक्षणों के लिए क्रमशः 100 रुपये व 300 रुपये प्रति शिक्षक प्रति दिन होता है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इतने कम बजट में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सम्भव है! सरकार ने शिक्षक प्रशिक्षण व अध्यापक शिक्षा की स्थिति को बेहतर करने की बजाए पिछले समय में 'स्वयं' नामक ऑन लाइन वेब पोर्टल शुरू कर दिया है। इस पर शिक्षकों के लिए 18 महीने के कोर्स शिक्षकों के लिए उपलब्ध हैं। शिक्षा केवल कुछ सिद्धांतों को पढ़ लेना भर नहीं है। इसमें मनुष्यों के बीच होने वाली अंतर्क्रिया महत्वपूर्ण है। जब तक शिक्षक स्वयं उस अंतर्क्रिया से नहीं गुजरेंगे हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे उसे अपने छात्रों के साथ अंजाम दे पाएंगे।

बताया जा रहा है कि हाल ही में शुरू हुए समग्र शिक्षा अभियान का एक उद्देश्य सेवा पूर्व व सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षणों को मदद करना भी है। मगर उसके लिए आवंटित कुल बजट का मात्र दो प्रतिशत ही अध्यापक शिक्षा के हिस्से आया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दूसरा संकेतक संसाधनों की उपलब्धता भी सन् 2015 तक आरटीई मानदंडों को पूरा करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहा है।

जब प्रधानमंत्री 'शिक्षा पे चर्चा' में टिप्पणी करते हैं कि शिक्षा प्रणाली ने ''शिक्षा को जीवन से काट दिया है और इसे परीक्षाओं से जोड़ दिया है'' तो यह खुद उनकी सरकार द्वारा फेल न करने की नीति को समाप्त कर दिए जाने पर सवाल खड़ा करती है और खुद उनकी सरकार के इस निर्णय को हास्यास्पद बना देती है।

पिछले पांच सालों में नीति आयोग का जोर परिणामोन्मुख रहा लेकिन उक्त तथ्य आपूर्ति या निवेश पर ध्यान न दिए जाने की दास्तान कहते हैं और बिना आपूर्ति व निवेश के बेहतर परिणामों की उम्मीद करना बेमानी हो जाता है।

पिछले पांच वर्षों में बजटों के माध्यम से कई वादे किए गए थे, कुछ को पूरा किया गया, तो कई को पर्याप्त संसाधनों नहीं मिले। उदाहरण के लिए, सीखने के अंतराल की पहचान करने के लिए, सरकार ने सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 701 जिलों के 1,10,000 स्कूलों के 20 लाख से ज्यादा छात्रों को शामिल करते हुए जिला स्तरीय राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण करने में सफलता हासिल की। वहीं, 2016 में, सरकार ने 62 नए जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। हाल ही में, जवाहर नवोदय विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए 5000 सीटें बढ़ाने की एक और घोषणा की गई है जबकि 2019-20 के लिए बजटीय आवंटन 2017-18 में हुए वास्तविक खर्च से भी कम किया गया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह मुंह बाए खड़ा है कि इन घोषणाओं को पार कैसे चढ़ाया जाएगा या फिर यह चुनावों के नक्कारे में एक तूंती की कराह मात्र बन कर रह जाने वाली हैं! ◆

प्रमोद